



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]
No. 466]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2003/आश्विन 4, 1925
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2003/ASVINA 4, 1925

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2003

सा.का.नि. 766(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (घ ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2001 का, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 575 (अ) तारीख 2 अगस्त, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) संशोधन नियम, 2003 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों) नियम, 2001 में,—

(i) नियम 4 में, "सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं, चिकित्सीय प्रसुविधाओं" शब्दों के स्थान पर "सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 4 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"4क अधिकारी और कर्मचारी निम्नवत चिकित्सीय प्रसुविधाओं के लिए हकदार होंगे, अर्थात्:—

(क) अधिकारी और कर्मचारी स्वयं और कुटुंब के घोषित सदस्यों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

स्पष्टीकरण:— इस खंड के प्रयोजन के लिए, "कुटुंब" पद का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 में उसे समनुदिष्ट है;

(ख) बाह्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, वास्तविक व्यय या उस वर्ष की एक जनवरी को एक मास के वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) जो भी कम हो, तक सीमित होगा। दावा डाक्टर के चिरभोग और डाक्टर द्वारा उपचार और औषधियों के क्रय के लिए मूल नकद रसीद या बिल द्वारा समर्थित होना चाहिए। वर्ष के दौरान वेतन वृद्धि या प्रोन्नति प्रदान करने पर 1 जनवरी की समाप्ति का प्रभाव, नहीं पड़ेगा। वर्ष के दौरान पद ग्रहण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वार्षिक हकदारी अनुपाततः आधार पर निर्बन्धित की जाएगी।

(ग) बाह्य उपचार अपील अधिकरण द्वारा पैनल पर रखे गए प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों से करवाया जाएगा।

(घ) अंतरंग चिकित्सीय उपचार के लिए अपील अधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी, इस निमित्त अपील अधिकरण द्वारा प्राधिकृत अस्पतालों में चिकित्सीय उपचार प्राप्त करने के हकदार होंगे और इस प्रयोजन के लिए उपचार, जिसके अंतर्गत अस्पताल

में स्थान सुविधा, परिचर्या गृह सुविधा आदि हैं, की लागत समतुल्य वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा लागू केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के उपबंधों के अनुसार होगी।

(ड) प्राधिकृत अस्पतालों में उपचार, आपात के सिवाय, प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारकों की सलाह पर करवाया जा सकेगा।

(च) इस नियम में वर्णित प्राधिकृत अस्पताल वही होंगे जो केन्द्रीय सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 द्वारा विनियमित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध हैं।”।

[फ.सं. 10-35/2000-पुनर्गठन]

पी. के. तिवारी, अवर सचिव (पुनर्गठन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2003

G.S.R. 766(E).— In exercise of powers conferred by Sub-section (1) read with clause (dc) of Sub-section (2) of Section 35 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (Salary, Allowances and other Condition of Service of the Officers and Employees) Rules, 2001, which were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* No. G.S.R. 575 (E), dated 2nd August 2001, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees) Amendment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

2. In the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (Salary, Allowances and other Conditions of Service of the Officers and Employees) Rules, 2001,—

(i) In rule 4, the words “retirement benefits, medical facilities” the words “retirement benefits” shall be substituted;

(ii) after rule 4, the following rule shall be inserted namely :—

“4A. The officers and employees shall be entitled to medical facilities as under, namely :—

(a) the officers and employees shall be eligible to get medical reimbursement for self and declared members of family;

Explanation.— For the purposes of this clause, the expression “family” has the same meaning as assigned to it in the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944;

(b) the reimbursement of outdoor medical expenses shall be limited to the actual expenses or one month’s pay on 1st January of the year (Basic pay + Dearness Allowance) whichever is less. The claim should be supported by Doctor’s prescription and the original cash memos or bills for treatment by the Doctor and purchase of medicines. Release of increment or promotion during the year shall not affect the limit as on 1st January. For officers and employees joining during the year, the annual entitlement shall be restricted on pro-rata basis;

(c) the outdoor treatment shall be taken from the Authorised Medical Attendants from the panel to be maintained by the Appellate Tribunal;

(d) the officers and employees of the Appellate Tribunal shall be entitled for indoor medical treatment at hospitals authorised by the Appellate Tribunal in this behalf, and for this purpose cost of treatment including hospital accommodation, nursing home facility, etc. shall be as per the provisions of the Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 as they are applicable to the Central Government employees drawing equivalent pay;

(e) the treatment at authorised hospital may be taken on the advice of the authorised Medical Attendants except in emergency;

(f) the authorised hospitals mentioned in this rule shall be the same as are available to the Central Government employees regulated by Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944.”

[F.No. 10-35/2000-Restg.]

P. K. TIWARI, Dy. Secy. (Restg.)